



Vidhi Rachnakar — Legal Draftsman (Rajasthan)

विधि रचनाकार वह अधिकारी है जो क़ानून का पाठ लिखता है। जब सरकार कोई नीति तय करती है, तो उसे विधेयक, अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के रूप में शब्दों में उतारने का काम विधि रचना संगठन करता है — और उस संगठन का प्रवेश-स्तर का पद यही है।...



इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-vidhi-rachnakar

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in



सुशील कुमार शर्मा

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer



श्री चेनाराम चौधरी

प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer



श्रीमती संघमित्रा

वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)



भरत चौधरी

अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS



सुरेन्द्र सिंह राठौड़

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना



सुरेश कुमार सैन

व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



वनिता कुमारी

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



कमलेश चौधरी

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14-17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14-17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

विधि रचनाकार वह अधिकारी है जो क़ानून का पाठ लिखता है। जब सरकार कोई नीति तय करती है, तो उसे विधेयक, अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के रूप में शब्दों में उतारने का काम विधि रचना संगठन करता है — और उस संगठन का प्रवेश-स्तर का पद यही है। काम में विधेयकों एवं नियमों का प्रारूपण, उनका हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों में समान अर्थ वाला पाठ तैयार करना, विभागों के प्रस्तावों की विधिक जाँच, तथा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सामग्री का परीक्षण आता है। यह अधिवक्ता का काम नहीं है — अधिवक्ता बने हुए क़ानून की व्याख्या न्यायालय में करता है, विधि रचनाकार वह क़ानून लिखता है जिसकी व्याख्या बाद में होगी। इसीलिए इस पद की कसौटी बहस नहीं, भाषा की सटीकता है: एक अस्पष्ट वाक्य वर्षों तक न्यायालयों में विवाद का कारण बन सकता है। इसी कारण चयन परीक्षा में कोई विधि का प्रश्न-पत्र नहीं है — दोनों प्रश्न-पत्र अनुवाद के हैं।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	विधि स्नातक (एल.एल.बी.) + बी.ए. परीक्षा में अंग्रेज़ी एवं हिन्दी दोनों विषय रहे हों (कम से कम एक ऐच्छिक के रूप में) — सेवा नियम 1981, अनुसूची-I
भर्ती संस्था	राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर — विभाग: विधि एवं विधिक कार्य / विधि रचना संगठन
आयु-सीमा	21 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को (सेवा नियम 1981) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% सीधी भर्ती — इस पद पर पदोन्नति से कोई नियुक्ति नहीं होती

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- भाषा, शब्दों की सटीकता एवं लेखन में रुचि
- क़ानून एवं नीति का काम, पर न्यायालय की बहस के बिना

- हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों में समान रूप से काम करना

क्षमताएँ

- दो भाषाओं में एक ही अर्थ बनाए रखने की क्षमता
- तार्किक ढाँचा बनाना, क्योंकि कानून का पाठ क्रम एवं संरचना पर टिका होता है
- अत्यंत सावधान पठन — अस्पष्टता को पहले ही पकड़ लेना

ज़रूरी कौशल

- विधायी प्रारूपण — विधेयक, अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना
- विधिक शब्दावली एवं मानक प्रारूपण परिपाटियाँ
- विभागीय प्रस्तावों की विधिक जाँच
- विधिक अनुवाद, अंग्रेज़ी से हिन्दी एवं हिन्दी से अंग्रेज़ी
- संविधान, विधायी प्रक्रिया एवं राजपत्र प्रकाशन की जानकारी
- संशोधन एवं प्रतिस्थापन की तकनीक — यही वह कौशल है जिससे पुराना एवं नया पाठ अलग रहता है

4 कैसे पहुँचें

- 1 कक्षा 12 उत्तीर्ण करें। कला संकाय इस राह के लिए सबसे स्वाभाविक है।
- 2 बी.ए. करें — और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आता है: बी.ए. में अंग्रेज़ी एवं हिन्दी दोनों विषय अवश्य लें (नियम के अनुसार कम से कम एक ऐच्छिक के रूप में)। यह पात्रता की शर्त है, वरीयता नहीं। जिस विद्यार्थी की बी.ए. में ये दोनों भाषाएँ नहीं रहीं, वह एल.एल.बी. कर लेने के बाद भी इस पद के लिए पात्र नहीं होगा — और तब तक यह निर्णय बदला नहीं जा सकता।
- 3 विधि स्नातक (एल.एल.बी.) करें — पुरानी योजना का 2 वर्षीय अथवा नई योजना का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, अथवा बी.एल. (प्रोफ़ेशनल), किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से।
- 4 दोनों भाषाओं में अनुवाद का अभ्यास करें, क्योंकि चयन परीक्षा पूरी तरह अनुवाद पर आधारित है। सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, संकल्प, अधिनियम एवं नियम — इन्हीं प्रकार की सामग्री का अनुवाद परीक्षा में आता है, और ये सब राजपत्र एवं विभागीय वेबसाइटों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- 5 हस्तलेख सुधारें। यह सलाह विचित्र लग सकती है, पर अनुसूची-II में स्पष्ट लिखा है कि खराब हस्तलेख पर अंक काटे जाएँगे।
- 6 आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए; आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- परीक्षा योजना नियमों की अनुसूची-II में पूरी दी गई है, और वह असामान्य है — इसमें विधि का कोई प्रश्न-पत्र नहीं है। दो प्रश्न-पत्र हैं और दोनों अनुवाद के: (1) अंग्रेज़ी से हिन्दी अथवा संविधान द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी अन्य भाषा में अनुवाद — 100 अंक; (2) हिन्दी अथवा उस अन्य भाषा से अंग्रेज़ी में अनुवाद — 100 अंक। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए 3 घंटे।
- और अनुसूची-II में एक वाक्य ऐसा है जो किसी अन्य भर्ती नियम में विरले ही मिलता है: "अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों में से खराब हस्तलेख के कारण कटौती की जाएगी।" यह असामान्य लगे तो यह याद रखें कि इस पद का उत्पाद ही लिखा हुआ पाठ है।
- योग्यता की शर्त पर एक बात दर्ज करने योग्य है। नियमों में इस शर्त का पुराना पाठ फुटनोट में उद्धृत है, जिसमें गुजराती, सिंधी, उर्दू अथवा पंजाबी में दक्षता रखने वालों को वरीयता देने का प्रावधान था। वह प्रावधान वर्तमान नियम में नहीं है (18.08.1989 की अधिसूचना से प्रतिस्थापित), इसलिए उसे आज की शर्त समझना भूल होगी।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।
- अनुसूची-II यह भी बताती है कि अनुवाद किस सामग्री का आएगा — प्रेस विज्ञप्तियाँ, समाचार-पत्रों के लेख, सरकारी संकल्प, विधान, नियम एवं अनुदेश; तथा ऐसी रचनाओं में प्रयुक्त सामान्य उक्तियों एवं रूढ़ प्रयोगों की व्याख्या भी पूछी जाती है। दूसरे प्रश्न-पत्र में समाचार-पत्रों के लेख एवं भाषण आते हैं।
- पद 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है — अनुसूची में इसके आगे पदोन्नति का कोई प्रतिशत नहीं है। संगठन में इससे ऊपर के सभी पद पदोन्नति से भरते हैं, इसलिए संवर्ग में प्रवेश केवल इसी द्वार से होता है।
- ध्यान दें — यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government law colleges, Rajasthan — LL.B. — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर (<https://hte.rajasthan.gov.in/>)
- University of Rajasthan — Faculty of Law, and B.A. with English and Hindi — जयपुर, राजस्थान (<https://uniraj.ac.in/>)
- National Law University, Jodhpur — जोधपुर, राजस्थान (<https://nlujodhpur.ac.in/>)
- Government colleges offering B.A. with both English and Hindi — the eligibility condition for this post — राजस्थान के सभी जिले (<https://hte.rajasthan.gov.in/>)

ऑनलाइन

- विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान — विधि रचना संगठन — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (<https://home.rajasthan.gov.in>)
- राजस्थान राजपत्र — अधिनियम एवं नियमों का प्रामाणिक पाठ, अनुवाद अभ्यास के लिए सर्वोत्तम निःशुल्क सामग्री — राजस्थान सरकार (<https://rajasthan.gov.in/>)
- India Code — Central and State Acts in both languages — भारत सरकार (<https://www.indiacode.nic.in/>)
- Legislative Department, Government of India — legislative drafting practice — भारत सरकार (<https://legislative.gov.in/>)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfls%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (<https://dop.rajasthan.gov.in/>)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (<https://swayam.gov.in/>)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (<https://ndli.iitkgp.ac.in/>)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (<https://ncert.nic.in/>)

फ्रीस

बी.ए. एवं एल.एल.बी. दोनों राजकीय महाविद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर हो जाते हैं, और राजस्थान के राजकीय विधि महाविद्यालय हर संभाग में हैं। इस पद की तैयारी की सामग्री लगभग पूरी तरह निःशुल्क है और यह इसकी सबसे व्यावहारिक विशेषता है: परीक्षा अनुवाद की है, और अनुवाद का अभ्यास राजपत्र, इंडिया कोड तथा विभागीय वेबसाइटों पर उपलब्ध द्विभाषी अधिनियमों एवं नियमों से किया जा सकता है — वही सामग्री जिससे प्रश्न बनते हैं। एक ही अधिनियम का हिन्दी एवं अंग्रेज़ी पाठ आमने-सामने रखकर पढ़ना इस परीक्षा की सबसे अच्छी तैयारी है और उस पर एक रुपया खर्च नहीं होता। परीक्षा शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (<https://sje.rajasthan.gov.in/>)
- National Scholarship Portal (NSP) (<https://scholarships.gov.in/>)
- Buddy4Study scholarship search (<https://www.buddy4study.com>)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

विधि रचना संगठन, सचिवालय, जयपुर। काम कार्यालय का है और लगभग पूरा लिखित — विभागों से आए प्रस्ताव, विधेयकों के प्रारूप, नियमों की अधिसूचनाएँ एवं राजपत्र की सामग्री।

कार्य-संस्कृति

यह शांत, एकाग्र और अत्यंत सावधानी वाला काम है, और उसका स्वभाव अधिवक्ता के पेशे से लगभग उल्टा है — यहाँ प्रतिद्वंद्विता नहीं, शुद्धता की माँग है। विधानसभा सत्र के समय दबाव तीव्र हो जाता है, क्योंकि विधेयक निश्चित तिथि तक तैयार होने ही हैं। काम का असर बहुत दूर तक जाता है और प्रायः अदृश्य रहता है: जो नियम आपने लिखा, वह वर्षों तक हर ज़िले में लागू रहेगा, और यदि उसका कोई वाक्य दो अर्थ देता है तो वही वाक्य आगे न्यायालयों में विवाद बनेगा। इसी कारण इस संगठन में संशोधन एवं प्रतिस्थापन की परिपाटी इतनी कठोर है — पुराना पाठ हटाते समय उसे फुटनोट में उद्धृत रखा जाता है, ताकि यह हमेशा पता रहे कि कब क्या बदला। जो व्यक्ति भाषा में सटीकता का आनंद लेता है, उसके लिए यह सरकार के भीतर सबसे संतोषजनक कामों में से एक है।

कौन नौकरी देता है

- विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान — विधि रचना संगठन
- राजस्थान सचिवालय — विधायी कार्य
- राजस्थान विधानसभा से संबद्ध विधायी कार्यवाही

माँग (2026)

यह एक छोटा एवं विशिष्ट संवर्ग है — नियमों की अनुसूची में विधि रचनाकार से ऊपर वरिष्ठ विधि रचनाकार, विधि रचना अधिकारी, उप सचिव, तथा संयुक्त सचिव एवं वरिष्ठ उप सचिव के पद हैं, और वे सब पदोन्नति से भरते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भर्ती तभी निकलती है जब प्रवेश-स्तर पर रिक्ति बनती है, इसलिए विज्ञप्ति अनियमित रहती है और पदों की संख्या कम। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा का दायरा भी उतना ही सीमित है: पात्रता के लिए एल.एल.बी. के साथ बी.ए. में अंग्रेज़ी एवं हिन्दी दोनों विषय होना आवश्यक है, और यह शर्त पूरी करने वाले विधि स्नातक अपेक्षाकृत कम होते हैं। जो विद्यार्थी बी.ए. के समय यह निर्णय सोच-समझकर ले लेता है, वह एक ऐसे संवर्ग में प्रवेश की पात्रता रखता है जिसमें बहुत से विधि स्नातक आवेदन ही नहीं कर सकते। यह भी ध्यान रखें कि पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

- 1 विधि रचनाकार — प्रवेश का पद, 100% सीधी भर्ती
- 2 वरिष्ठ विधि रचनाकार — विधि रचनाकार के पद पर 5 वर्ष की सेवा पर, पदोन्नति से
- 3 विधि रचना अधिकारी — वरिष्ठ विधि रचनाकार के पद पर 5 वर्ष की सेवा पर, पदोन्नति से
- 4 उप सचिव (विधि रचना संगठन) — 100% पदोन्नति से
- 5 संयुक्त सचिव एवं वरिष्ठ उप सचिव — सेवा में क्रमशः 27 एवं 30 वर्ष के अनुभव पर

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹60,000 – ₹80,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹1,00,000 से अधिक (भत्तों सहित, उप सचिव एवं उससे ऊपर)

1981 के सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया — वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा। यह विधि स्नातक की योग्यता वाला सचिवालय-स्तर का पद है और इसकी पदोन्नति सीढ़ी उप सचिव तथा संयुक्त सचिव तक जाती है, इसलिए दीर्घकाल में वेतन अच्छा रहता है — पर यह ध्यान रहे कि वह सीढ़ी लंबी है, संयुक्त सचिव के लिए नियमों में ही 27 वर्ष का अनुभव लिखा है। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें • चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- क़ानून एवं नीति का काम, न्यायालय की प्रतिद्वंद्विता एवं अनिश्चित आय के बिना
- तैयारी की सामग्री लगभग पूरी तरह निःशुल्क एवं आधिकारिक — द्विभाषी अधिनियम एवं नियम
- परीक्षा में विधि का प्रश्न-पत्र नहीं, इसलिए तैयारी का दायरा स्पष्ट एवं सीमित है
- पात्रता की शर्त संकीर्ण है, जिससे प्रतिस्पर्धा का दायरा भी संकीर्ण रहता है
- काम का प्रभाव दीर्घकालिक — लिखा हुआ नियम वर्षों तक लागू रहता है

चुनौतियाँ

- बी.ए. में अंग्रेज़ी एवं हिन्दी दोनों की शर्त — यह निर्णय स्नातक के समय ही हो जाता है और बाद में सुधारा नहीं जा सकता
- संवर्ग बहुत छोटा है और भर्ती अनियमित
- काम एकाकी एवं अत्यंत सूक्ष्म — यह सबके स्वभाव के अनुकूल नहीं
- पदोन्नति की सीढ़ी लंबी है; नियमों में ही संयुक्त सचिव हेतु 27 वर्ष का अनुभव लिखा है
- नियुक्ति मुख्यतः जयपुर सचिवालय में — ज़िला स्तर पर यह पद नहीं होता

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- न्यायाधीश
- सहायक अभियोजन अधिकारी (राजस्थान)
- कनिष्ठ विधि अधिकारी (राजस्थान)

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202305050509526211246vidhirachnapdf24_merged.pdf

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग — विज्ञप्तियाँ — <https://rpssc.rajasthan.gov.in/advertisements>
3. गृह विभाग, राजस्थान — विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अपनी साइट वर्तमान में उपलब्ध नहीं — <https://home.rajasthan.gov.in>
4. इंडिया कोड — केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम, दोनों भाषाओं में — <https://www.indiacode.nic.in/>
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — <https://rssb.rajasthan.gov.in/>
6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — <https://dop.rajasthan.gov.in/>
7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289>



और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in